UPSC Prelims- 2019

भारत की राजव्यवस्था

पूछे गए प्रश्न

विस्तृत समाधान

सही दृष्टिकोण

PrepMate भारत की राजव्यवस्था पुस्तक का प्रदर्शन

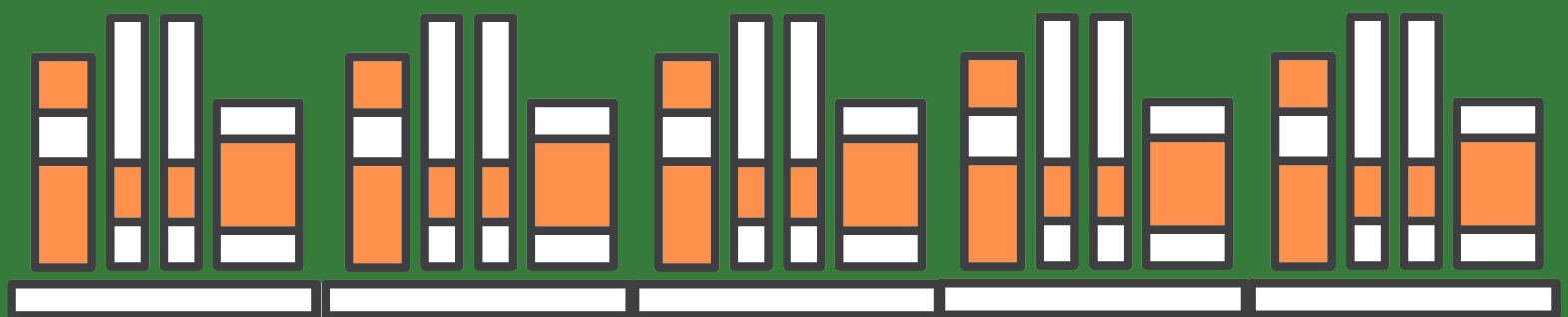

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया।

2. भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Sol. 1 (b) केवल 2

स्रोत: PrepMate भारत की राजव्यवस्था, अध्याय 25, पृष्ठ 306 और अध्याय 8, पृष्ठ 150

कथन 1 गलत है। PrepMate भारत की राजव्यवस्था, अध्याय 25, पृष्ठ 306

44वां संशोधन अधिनियम, 1978

- 42वें संशोधन अधिनियम के तहत पारित संशोधनों को पलट दिया, जिनके लागू होने से प्रशासन में केंद्रीयकरण हुआ था। उदाहरण के लिए, लोकसभा और विधान सभाओं का कार्यकाल वापस 5 साल कर दिया गया था।
- राष्ट्रीय आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को समाविष्ट किया गया था।
- मौलिक अधिकार के रूप में संपदा अधिकार को समाप्त कर दिया तथा इसे अनुच्छेद 300क के तहत संविधान में डाल दिया गया था।
- अनुच्छेद 74 के तहत, यह प्रदान किया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् के पुनर्विचार के लिए सलाह भेज सकते हैं।

कथन 2 गलत है। PrepMate भारत की राजव्यवस्था, अध्याय 8, पृष्ठ 158

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की वर्तमान स्थिति (Present Status of NJAC)

सर्वोच्च न्यायालय ने 99 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 'असंवैधानिक' बताया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक कार्यकारी के साथ साझा नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की अपेक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखना और शासन के अन्य अंगों से अछूता रखना आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली परिचालित रहेगी। लेकिन यह स्वीकार किया कि कॉलेजियम प्रणाली के तहत, न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति ठीक नहीं है और समय न्यायिक नियुक्तियों की पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए परिपक्व है।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

2. भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या-क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की 'अक्षमता और सिद्ध कदाचार' को गठित करते हैं।

3. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में दिए गए हैं।

4. यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई द्वारा समर्थित हो।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2

(b) केवल 3

(c) केवल 3 और 4

(d) 1, 3 और 4

Sol. 2 (c) केवल 3 और 4

2 और 4 कथन के लिए स्रोत: PrepMate भारत की राजव्यवस्था, अध्याय 8, पृष्ठ 158-159

कथन 2 गलत है। भारत का संविधान यह परिभाषित नहीं करता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार क्या है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना (Removal of Judges of Supreme Court)

अनुच्छेद 124 (4): संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत, यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन का आदेश जारी कर सकता है। संसद के सदन केवल न्यायाधीश के सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर ऐसा प्रस्ताव पारित कर सकते हैं।

इसके अलावा न्यायाधीश की निष्कासन की पूरी प्रक्रिया एक सत्र के दौरान हो जानी चाहिए। एक सत्र में प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए क्योंकि जब तक कार्यवाही पूरी नहीं होती, न्यायाधीश को कार्य नहीं करने दिया जाता। फलस्वरूप, निष्कासन की कार्यवाही में देरी से न्यायपालिका के कामकाज में रुकावट आती है। इसके अलावा, न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए कार्यवाही की लंबितता का उपयोग किया जा सकता है।

कथन 4 सही है। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग का प्रस्ताव मतदान के लिए लिया जाता है, तो प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई द्वारा समर्थित हो।

कथन 3 सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में दिए गए हैं।

कथन 1 गलत है। न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।

3. किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची को पुरःस्थापित किया गया था?

(a) जवारहलाल नेहरू

(b) लाल बहादुर शास्त्री

(c) इंदिरा गाँधी

(d) मोरारजी देसाई

Sol. 3 (a) जवारहलाल नेहरू

स्रोत:PrepMate भारत की राजव्यवस्था, अध्याय 5, पृष्ठ 46

17वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, *1964 (17th Constitutional Amendment Act, 1964)*

संसद ने 1964 में 17वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया। इस संशोधन में 9 वीं अनुसूची के तहत राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ कानून शामिल किए गए थे। जैसा कि 9 वीं अनुसूची के तहत कानून लागू किया जा सकता है, भले ही वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इस संशोधन के कारण, मौलिक अधिकारों का दायरा कम हो गया।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कई पदों को 'लाभ का पद' के आधार पर निरर्हता से छूट देता है।

2. उपर्युक्त अधिनियम पाँच बार संशोधित किया गया था।

3. शब्द 'लाभ का पद' भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

Sol. 4 (a) केवल 1 और 2

स्रोत: PrepMate भारत की राजव्यवस्था, अध्याय 8, पृष्ठ 76

इस प्रश्न को केवल कथन 3 के आधार पर हल किया जा सकता है।

कथन 3 गलत है। भारत के संविधान में 'लाभ का पद'शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द को परिभाषित किया है।

'लाभ का कार्यालय' क्या है? (What is 'Office of Profit'?)

लाभ का कार्यालय एक ऐसा पद है जो पद धारक को कोई वित्तीय या अन्य लाभ प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, भले ही कोई पदाधिकारी किसी भी वित्तीय लाभ के बिना पद धारण करता है, फिर भी इसे लाभ का कार्यालय माना जाएगा।

दूसरे शब्दों में, लाभ का कार्यालय केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, या स्थानीय निकाय के तहत कार्यकारी कार्यालय को दर्शाता है। स्वायत्त निकायों में कार्यालय के धारक को लाभ का कार्यालय धारक नहीं माना जाता है।

लाभ के कार्यालय के धारक ने सरकार के तहत काम किया है और, इसीलिए, वह सरकार के प्रभाव के बिना स्वतंत्र रूप से कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं माना जाता है। इस प्रकार, लाभ का कार्यालय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक अयोग्यता है।

5. भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है?

(a) तीसरी अनुसूची

(b) पाँचवीं अनुसूची

(c) नौवीं अनुसूची

(d) बारहवीं अनुसूची

Sol. 5 (b) पाँचवीं अनुसूची

स्रोत: PrepMate भारत की राजव्यवस्था, अध्याय 28, पृष्ठ 324

पांचवीं अनुसूची राज्य के राज्यपाल को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देती है कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन आदिवासियों के हित में हो।

पांचवी अनुसूची (Fifth Schedule)

असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान:

1. राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने या निर्धारित करने या खंडन करने का अधिकार है।
2. राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए राज्य को निर्देश देने का अधिकार है।
3. राज्यपाल को प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति चाहे, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता है।
4. राज्यपाल अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के मामले में सलाह लेने के लिए 'जनजाति सलाहकार परिषद्' (Tribes Advisory Council) का गठन करेगा।
5. राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् के परामर्श से कानून बना सकता है।
6. केंद्रीय विधान मंडल या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित कानून जनजातीय समुदायों पर लागू नहीं होगा या इस तरह के संशोधनों के साथ लागू होगा, जैसे राज्यपाल द्वारा जरूरी समझा जाता है।

6. भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी।

2. भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Sol. 6 (d) न तो 1, न ही 2

इस प्रश्न का उत्तर PrepMate भारतीय राजव्यवस्था या PrepMate Current Affairs को पढ़कर दिया जा सकता है।

कथन 1 गलत है: भारतीय संविधान ने एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली की स्थापना की है जिसमें शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय और उसके नीचे राज्य उच्च न्यायालय हैं। अदालतों की यह एकल प्रणाली दोनों केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य के कानूनों को लागू करती है और उनकी समीक्षा करती है। इस प्रकार, उच्च न्यायालयों को किसी भी केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित करने का अधिकार क्षेत्र है। वैकल्पिक रूप से, हाल के दिनों में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब उच्च न्यायालयों ने केंद्रीय कानून को संवैधानिक रूप से अमान्य घोषित किया है।

PrepMate ने जनवरी 2019 से हिंदी समाचार विश्लेषण करना शुरू किया है। इस प्रकार, उससे पहले की खबरों के स्रोत PrepMate English News juice से लिए गए हैं।

Why are parties in Tamil Nadu against 10% quota? (Relevant for GS Prelims, GS Mains Paper II; Polity & Governance)

February 4, 2019
By Admin

What is their stand?

The 103rd Constitution Amendment, through which the Centre has introduced a 10% quota for the economically weaker sections among communities that do not enjoy any other form of reservation, has drawn near universal opposition from almost all major parties in Tamil Nadu. When it was introduced as the 124th Constitution (Amendment) Bill in Parliament, the AIADMK, the ruling party in the State, and considered to be friendly towards the BJP, spoke out against it in both Houses of Parliament. Its MPs walked out during the vote. Kanimozhi, DMK MP, moved a motion to refer the Bill to a select committee, but it was defeated. R.S. Bharathi, organising secretary of the DMK, has challenged the amendment in the Madras High Court. The Viduthulai Chiruthaigal Katchi (VCK), an ally of the DMK, has moved the Supreme Court against it. D. Veerasekaran, an advocate who belongs to the Dravidar Kazhagam, has also approached the High Court.

कथन 2 भी गलत है: सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले (1973) में कहा कि संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह संविधान के 'बुनियादी ढांचे' का उल्लंघन करता है और इसलिए इसे शून्य घोषित किया जा सकता है।

स्रोत: PrepMate भारत की राजव्यवस्था, अध्याय 5, पृष्ठ 45

मौलिक अधिकारों के संशोधन की सीमा (Extent of Amendability of Fundamental Rights)

सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले (1974) में कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। संशोधन मौलिक अधिकारों में भी किया जा सकता है। परंतु, कोई भी संशोधन संविधान के 'बुनियादी ढांचे या आधारिक संरचना या मूल संरचना के सिद्धांत (Doctribe of Basic Structure)' के अधीन होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी ढांचे को परिभाषित नहीं किया है और न ही संविधान के बुनियादी ढांचे के तत्वों की कोई संपूर्ण सूची दी है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने, अपने विभिन्न निर्णयों में, उल्लेख किया है कि निम्नलिखित प्रावधान संविधान के बुनियादी ढांचे का एक तत्व हैं:

1. भारत की संप्रभुता (Sovereignty of India)
2. धर्मनिरपेक्षता (Secularism)
3. लोकतंत्र (Democracy)
4. गणतंत्र (Republic)
5. विमुक्त और निष्पक्ष चुनाव (Free and fair elections)
6. न्यायिक समीक्षा, आदि। (Judicial review, etc.)

यह सूची प्रकृति में समावेशी (inclusive) अथवा गैर-संपूर्ण (non-exhaustive) है।

इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि मूल ढांचे में और तत्व जोड़े जा सकते हैं, लेकिन कोई भी तत्व विलोपन (deletions) नहीं किया जा सकता है।

इसके इलावा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 99 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम असंवैधानिक और शून्य घोषित किया था। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना के प्रावधान थे।

स्रोत: PrepMate भारत की राजव्यवस्था, अध्याय 8, पृष्ठ 158

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की वर्तमान स्थिति (Present Status of NJAC)

सर्वोच्च न्यायालय ने 99 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 'असंवैधानिक' बताया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक कार्यकारी के साथ साझा नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की अपेक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखना और शासन के अन्य अंगों से अछूता रखना आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली परिचालित रहेगी। लेकिन यह स्वीकार किया कि कॉलेजियम प्रणाली के तहत, न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति ठीक नहीं है और समय न्यायिक नियुक्तियों की पुरानी व्यवस्था को बदलने के लिए परिपक्व है।

7. राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे?

(a) राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरूद्ध संरक्षण

(b) नियंत्रण का अभाव

(c) इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर

(d) स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर

Sol. 7 (d) स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर

Prelims 2017 और 2018 में भी स्वतंत्रता की अवधारणा पर प्रश्न पूछे गए हैं। PrepMate भारत की राजव्यवस्था पुस्तक में इन प्रश्नों का विस्तृत विवरण है। हालाँकि, हम इस प्रश्न के अपनी अध्ययन सामग्री में शामिल होने का दावा नहीं करते हैं। यह प्रश्न अवधारणाओं के गहन सैद्धांतिक ज्ञान की मांग करता है। आइए हम उत्तर विकल्पों की जांच करें।

विकल्प (a) गलत है: यह स्वतंत्रता के पूर्ण विचार को व्यक्त करने में विफल है। राजनीतिक शासकों के अत्याचार के खिलाफ संरक्षण स्वतंत्रता के पूर्ण विचार को व्यक्त नहीं करता है। स्वतंत्रता न केवल संरक्षण प्रदान करती है, बल्कि यह विविध प्रकार की स्वाधीनता को भी संभव करती है।

विकल्प (b) गलत है: यदि कोई नियंत्रण नहीं हो, तो एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार, सभी व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए नियंत्रण आवश्यक है। उदाहरण के लिए, मौलिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध है। वाक् स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर 8 सीमाएँ हैं।

विकल्प (c) गलत है: यह भी बिना किसी नियंत्रण के स्वतंत्रता देने का प्रयास करता है। विकल्प (b) को गलत साबित करने के लिए दिया गया स्पष्टीकरण विकल्प (c) के लिए भी लागू है।

विकल्प (d) सही है: स्वतंत्रता (नियंत्रण के साथ) हमें जीवन में पूरी तरह से विकसित होने का अवसर प्रदान करती है। विकास विभिन्न आयामों जैसे सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक आदि में हो सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक विकसित व्यक्ति में नियंत्रण के लिए अत्यधिक सम्मान होता है क्योंकि गतिविधियों पर नियंत्रण अन्य लोगों को अपनी स्वतंत्रता का आनंद लेने में सक्षम बनाता है।

8. भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते/करती हैं?

1. संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियाँ

2. संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ

3. वित्त आयोग

4. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग

5. नीति (NITI) आयोग

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएः

(a) 1 और 2

(b) 1, 3 और 4

(c) 3, 4 और 5

(d) 2 और 5

Sol.8 (a) 1 और 2

स्रोत: PrepMate राजव्यवस्था पुस्तक, अध्याय 8, पृष्ठ 143 तथा 144

यह एक अप्रत्यक्ष प्रश्न है। इस प्रश्न में उल्लिखित निकायों के कामकाज के बारे में समझने की आवश्यकता है।

कथन 1 सही है: किसी विशेष मामले पर सलाह और पूछताछ के लिए संसद की तदर्थ समितियों की स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार, उन्हें स्वतंत्र नियामकों की समीक्षा के लिए स्थापित किया जा सकता है।

तदर्थ समितियां

तदर्थ समितियां दो प्रकार की होती हैं:

1. **जांच समितियां (Inquiry committees):** इन्हें समय-समय पर किसी खास विषय की जांच करने के लिए दो सदनों द्वारा या पीठासीन अधिकारी द्वारा गठित किया जाता है। उदाहरण के लिए, बोफोर्स अनुबंध, 2 जी स्पेक्ट्रम आदि।

   जांच समिति प्रवर समिति (Select Committee) या संयुक्त समिति (Joint Committee) हो सकती है। चयन समिति में किसी एक सदन से सदस्य होते हैं और संयुक्त समिति में दोनों सदनों से सदस्य होते हैं। संसद में प्रतिनिधित्व के आधार पर, संयुक्त समिति की सदस्यता में विभिन्न राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

2. **सलाहकार समितियां (Advisory committees):** ये विशेष मामले पर सुझाव देने के लिए गठित की जाती है। ये समितियां मामले का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती हैं। सलाहकार समिति भी चयन या संयुक्त समिति हो सकती है।

कथन 2 सही है: संसदीय विभाग संबंधित स्थायी समितियाँ विशेष मंत्रालय/विभाग के कामकाज, खातों और बिलों की समीक्षा करती हैं। इस प्रकार, वे विशेष विभाग से संबंधित स्वतंत्र नियामक की समीक्षा भी कर सकती हैं।

2. **विभागीय स्थायी समितियां (Departmental Standing Committees):** केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 24 स्थायी समितियां हैं। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं (21 लोकसभा और 10 राज्यसभा से)। लोक सभा के सदस्यों को स्पीकर द्वारा नामित किया जाता है और राज्य सभा के सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। एक मंत्री, विभागीय स्थायी समिति का सदस्य होने के योग्य नहीं है। विभागीय स्थायी समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष होता है (वित्तीय समितियों के सदस्य की तरह)।

   विभागीय स्थायी समिति निम्नलिखित कार्य करती हैं:

   (a) यह विशेष विभाग/मंत्रालय द्वारा की गई वित्तीय की मांग की जांच करती है।

   (b) यह किसी विशेष विभाग/मंत्रालय से संबंधित विधेयक की जांच करती है।

   (c) यह मंत्रालय/विभाग आदि की वार्षिक रिपोर्ट का निरीक्षण करती है।

कथन 3 गलत है: वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच धन के विभाजन की सिफारिश करता है। यह स्वतंत्र नियामकों की समीक्षा नहीं करता है।

कथन 4 गलत है: वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सिफारिशें करता है।

कथन 5 गलत है: नीति आयोग ने कई कार्य किए हैं जैसे कि सरकारी तंत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, कुछ कार्यों की देखरेख, मुद्दों पर सिफारिशें, आदि। हालांकि, यह स्वतंत्र नियामकों की समीक्षा में शामिल नहीं है।

9. भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक, इसका अर्थ हो सकता है?

(a) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

(b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा विधियों से बाध्य नहीं होता।

(c) देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है।

(d) कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल, संघ विधानमंडल की सहमति के बिना, विधि निर्मित नहीं कर सकते।

Sol. 9 (b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा विधियों से बाध्य नहीं होता।

स्रोत: PrepMate भारत की राजव्यवस्था, अध्याय 8, पृष्ठ 161

6. **अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन (Enforcement of decrees and orders of Supreme Court):** अनुच्छेद 142 में यह बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता में ऐसी डिक्री या आदेश दे सकता है, जैसा कि किसी उसके सामने लंबित मामले में पूरा न्याय करने के लिए जरूरी है। इस तरह की डिक्री या आदेश पूरे भारत में लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 142 के प्रावधान न्यायिक सक्रियता का आधार हैं।

यह एक दिलचस्प सवाल है। इस प्रश्न के लिए अनुच्छेद 142 और प्रश्न में दी गई जानकारी के संयुक्त विश्लेषण की आवश्यकता है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए असाधारण शक्तियाँ प्रदान करता है। अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून से बाध्य नहीं है।

10. भारत के किसी राज्य की विधान सभा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

1. वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है।

2. जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता, तो उस विषय पर वह लोक सभा के नियम का पालन करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1, न ही 2

Sol. 10 (a) केवल 1

कथन 1 का स्रोत: PrepMate भारत की राजव्यवस्था, अध्याय 8, पृष्ठ 128 and अध्याय 9, पृष्ठ 173

राष्ट्रपति का संबोधन (President's Address)

राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ प्रत्येक बजट सत्र की पहली बैठक में और नव गठित लोकसभा की पहली बैठक में संबोधित करता है। राष्ट्रपति के भाषण में दोनों सदनों द्वारा एक साथ भाग लिया जाता है, लेकिन इसे संसद के दोनों सदनों की संयक्त बैठक के रूप में नहीं माना जाता है।

राज्यपाल (Governor)

राज्यपाल की भूमिका (Role of Governor)

राज्य स्तर पर राज्यपाल का कार्यालय संघ स्तर पर राष्ट्रपति के कार्यालय के समान है। राष्ट्रपति संघ का प्रमुख है। इसी तरह, राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। हालांकि, राज्यपाल राज्य के प्रमुख होने के अलावा कई भूमिकाएं निम्नानुसार निभाता है:

कथन 2 गलत है। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम

(1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल का कोई सदन अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा।

(2) जब तक खंड (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले तत्स्थानी प्रांत के विधान-मंडल के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे वे ऐसे उपान्तरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए उस राज्य के विधान-मंडल के संबंध में प्रभावी होंगे जिन्हें, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति उनमें करे ।